दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काज़ी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom

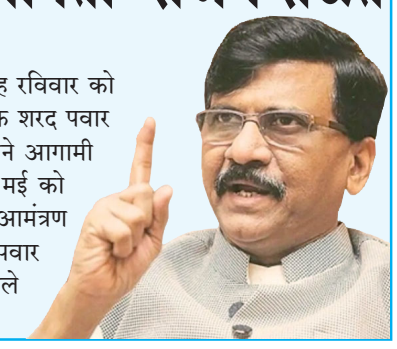

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२७६ वा | मंगळवार ६ मे २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

...तो बैठक में अमित शाह का इस्तीफ़ा मांगता-संजय राऊत

/ जमीर काज़ी,
मुंबई, ५ मई

पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मैं जानबूझकर शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर गया होता तो गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफ़ा मांगता और तब हम सभी को मुश्किल में डाल देता-यह बात शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद संजय राऊत ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।

संजय राऊत ने बताया कि वह रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार से मिलने पहुंचे थे ताकि उन्हें अपने आगामी पुस्तक 'नरकातील स्वर्ग' के १७ मई को होने वाले विमोचन कार्यक्रम का आमंत्रण दे सकें। इस मुलाकात के दौरान पवार और राऊत के बीच पहलगाम हमले को लेकर भी चर्चा हुई।

गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को ७ मई को 'मॉक ड्रिल' आयोजित करने के दिए निर्देश

दुश्मन हमले की स्थिति से निपटने के लिए देशभर में तैयारियाँ तेज़

नई दिल्ली, ५ मई । संवाददाता

पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ७ मई को कई राज्यों में 'मॉक ड्रिल' (अभ्यास सत्र) आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को जानकारी दी कि यह अभ्यास देश की आंतरिक सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी को मज़बूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, मॉक ड्रिल के तहत निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

हवाई हमले की चेतावनी सायरनों को सक्रिय करना

नागरिकों व छात्रों को आत्म-सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण देना

क्रैश ब्लैकआउट की प्रक्रिया का अभ्यास

महत्वपूर्ण संयंत्रों और संस्थानों के त्वरित खालीकरण और सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना को अपडेट कर उसका रिहर्सल करना

गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्य सरकारों से अपील की है कि वे अपने इवैक्यूएशन (निकासी) प्लान्स को अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि आपात स्थिति में तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं, जिनमें शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। यह बैठकें २२ अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद हो रही हैं, जिसमें २६ नागरिकों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक शामिल थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपराधियों और षड्यंत्रकारियों को धरती के अंतिम छोर तक पीछा करके, उनकी कल्पना से परे सज़ा दिलाएंगे।

आख़िरकार विधायक संदीप क्षीरसागर और पूर्व विधायक सैयद सलीम ने बीड़ की जलसंकट से दिलाई राहत!

अब बीड़ शहर को सप्ताह में एक बार नियमित रूप से मिलेगा पानी

बीड़, ५ मई । विशेष संवाददाता

करीब साढ़े तीन लाख की आबादी वाला बीड़ शहर अब जलसंकट से राहत की ओर बढ़ रहा है। वर्षों से प्यासे शहरवासियों को आखिरकार उम्मीद की किरण नजर आई है। विधायक संदीप क्षीरसागर और पूर्व विधायक सैयद सलीम की लगातार कोशिशों के चलते अब बीड़ शहर को सप्ताह में एक बार नियमित पानी मिलना तय हुआ है।

ज्ञात हो कि बीड़ शहर में पर्याप्त जलस्रोत उपलब्ध होने के बावजूद लोगों को महीनों तक पानी नहीं मिल रहा था। यह संकट केवल श्रेय की राजनीति और तकनीकी अड़चनों के कारण बना हुआ था। लेकिन विधायक संदीप क्षीरसागर और पूर्व विधायक सैयद सलीम ने इसे गंभीरता से लिया और व्यक्तिगत स्तर पर लगातार प्रयास किए।

शहर को जलापूर्ति करने वाली पुरानी पाइपलाइन, जो लगभग २० साल पुरानी है, उसमें ७५० मीटर की पाइपलाइन पूरी तरह से जंग लगकर खराब हो चुकी थी। बीते एक महीने में भीषण गर्मी (४२ डिग्री तापमान) के बीच, दिन-रात मेहनत करके दोनों नेताओं ने स्वयं खड़े रहकर पाइपलाइन की मरम्मत करवाई।

इतना ही नहीं, जलापूर्ति में बाधा बन रही बिजली आपूर्ति की तकनीकी समस्या को भी सुलझा लिया गया है। इसके चलते अब बीड़ शहर को हर ६ दिन में नियमित रूप से जलापूर्ति मिल सकेगी।

इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को लेकर शहर में संतोष और राहत का माहौल है। नागरिकों ने दोनों जनप्रतिनिधियों की सराहना की है, जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में ठोस कार्य किया।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई स्थगित - अब १५ मई को अगली तारीख, नए उगख गवई के समक्ष होगी सुनवाई

नई दिल्ली, ५ मई २०२५ । विशेष संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, २०२५ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज (सोमवार) को सुनवाई स्थगित कर दी। अब यह मामला १५ मई २०२५ को न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुना जाएगा।

दरअसल, मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना १३ मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और न्यायमूर्ति गवई उनके उत्तराधिकारी के रूप में देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस पृष्ठभूमि में अदालत ने यह महत्वपूर्ण मामला उनकी नई पीठ को सौंपने का निर्णय लिया।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता की आवश्यकता है और इस चरण में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। सभी पक्षों की सहमति से मामला न्यायमूर्ति गवई की अगुवाई वाली पीठ को सौंपने पर सहमति बनी।

केंद्र सरकार का पक्ष

सरकार ने १,३३२ पन्नों के हलफनामे में कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं और पवित्र स्थलों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया है। सरकार का कहना है कि वक्फ बाय यूज़र की प्रक्रिया १९२३ से प्रचलित है, और २०१३ के संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों की कुल ज़मीन में २० लाख एकड़ की वृद्धि हुई है।

याचिकाकर्ताओं की आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट में अब तक लगभग ७० याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य संगठनों की याचिकाएं शामिल हैं।

याचिकाओं में 'वक्फ बाय यूजर' के प्रावधान और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर आपत्ति जताई गई है।

पिछली सुनवाई में सरकार ने क्या कहा था? १७ अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि ५ मई तक वक्फ संपत्तियों को वक्फ बाय यूज़र घोषित नहीं किया जाएगा, और न ही वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में नई नियुक्तियाँ की जाएंगी। यह आश्वासन कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया था।

अब यह संवेदनशील और बहुचर्चित मामला १५ मई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, जब न्यायमूर्ति बी. आर. गवई देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल चुके होंगे।

मिल्लिया जूनियर कॉलेज बीड़ का बारहवीं का शानदार रिजल्ट

डेटलाइन: बीड़ । काजी नासेर

मिल्लिया जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड वोकेशनल, बीड़ ने इस वर्ष २०२५ की क्ढउ परीक्षा में एक बार फिर अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शानदार परिणाम हासिल किया है।

कॉलेज द्वारा जारी किए गए आँकड़ों के अनुसार-

साइंस फैकल्टी का कुल परिणाम ९९.३३% रहा,

आर्ट्स फैकल्टी का परिणाम ९०.१०%, जबकि वोकेशनल फैकल्टी का परिणाम ८६.५३% दर्ज किया गया।

उस कामयाबी पर सचिव सबीहा खान बाजी , अध्यक्ष डॉ सलीम बिन महफुज,

कॉलेज के प्राचार्य फैसल चाउस , प्राध्यापकगण एवं प्रबंधन की ओर से सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी गई है। साथ ही इस शानदार उपलब्धि के पीछे शिक्षकों की मेहनत, विद्यार्थियों की लगन और अभिभावकों का सहयोग प्रमुख कारण बताया गया।

शैक्षणिक क्षेत्र में मिल्लिया कॉलेज बीड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अनुशासन, समर्पण और गुणवत्ता के साथ काम किया जाए तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह परिणाम पूरे बीड़ ज़िले के लिए गर्व की बात है।

राहुल गांधी को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जानिए क्या थी वजह

लखनऊ, ६ मई । विशेष संवाददाता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाले मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (झखङ) को खारिज कर दिया।

यह फैसला जस्टिस अता रहमान मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ता की शिकायत के निपटारे के लिए कोई निश्चित समय सीमा देने में असमर्थ है, ऐसे में याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

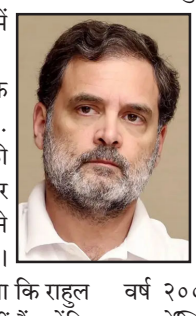

क्या था याचिका में दावा?

यह याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. वग्नेश शिशिर ने दायर की थी। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त की है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ९ और नागरिकता अधिनियम १९५५ का उल्लंघन है।

अनुच्छेद ९ के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, वह भारत का नागरिक नहीं रह सकता।

क्या था मुख्य आधार?

याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में वर्ष २००३ में स्थापित एक कंपनी इरलज़्ज़ीी ड्ळाळींशव के दस्तावेजों में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने मुख्य चुनाव आयुक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश देने की मांग की थी कि राहुल गांधी का चुनाव प्रमाणपत्र रद्द किया जाए। कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगने के बाद याचिका को निपटा दिया और फिलहाल इस विवाद को समाप्त कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अन्य वैधानिक विकल्प अपनाने की अनुमति दी है, यानी वह कानूनी रूप से अन्य उपायों का सहारा ले सकता है।

बीड का पानी संकट जल्द होगा दूर; संरक्षक मंत्री अजित पवार ने जिलाधिकारी को दिए तत्काल निर्देश

डॉ. योगेश क्षीरसागर की मांग पर त्वरित कार्रवाई, जल्द समाधान की उम्मीद

प्रतिनिधि । बीड़, ५ मई

बीड शहर में गहराते जलसंकट को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता डॉ. योगेश क्षीरसागर ने राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं बीड़ के संरक्षक मंत्री अजितदादा पवार से चर्चा कर तत्काल उपाय योजना की मांग की। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए अजित पवार ने तुरंत बीड़ जिलाधिकारी को फोन कर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इससे शहर की पानी की समस्या के जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।

बीड शहर के नागरिकों को पिछले कुछ महीनों से नियमित और समय पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे उन्हें भारी

परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी हैं। जनता की चिंता को ध्यान में रखते हुए डॉ. योगेश क्षीरसागर ने यह मुद्दा संरक्षक मंत्री अजित पवार के समक्ष रखा। सूत्रों के अनुसार, अजित पवार द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रशासन की जल आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए संबंधित यंत्रणा सक्रिय हो चुकी है। प्रशासन की ओर से शीघ्र ही जल वितरण व्यवस्था को सुचारू करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

इस विकास के बाद शहरवासियों में संतोष का वातावरण है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही बीड़ शहर की जल संकट की समस्या का समाधान हो जाएगा।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वो साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

प्रशासन को अधिक सक्षम और गतिशील बनाने हेतु टेक वारी' मार्गदर्शक साबित होगा-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, ५ मई । विशेष संवाददाता

प्रशासन यदि समयानुसार बदलाव स्वीकार करे, तो जनता को तेज़, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। इस विचार के साथ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज मंत्रालय स्थित त्रिमूर्ति प्रांगण में टेक वारी: महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक' का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उनकी क्षमताओं के विकास में मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

इस अवसर पर सूचना व तकनीकी मंत्री ड. आशीष शेलार, प्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार, महाराष्ट्र सदन की आयुक्त आर. विमला, प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता प्रभु गौर गोपाल दास समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार का वक्तव्य:

५ से ९ मई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर विशेषज्ञ सरल और प्रभावशाली तरीके से मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही तनाव प्रबंधन, म्यूजिक थैरेपी, ध्यान और कार्य-जीवन संतुलन जैसे सत्रों से संतुलित और सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करने की दिशा में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, हम केवल बदलावों को स्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि उनका नेतृत्व कर रहे हैं।

आशीष शेलार का वक्तव्य:

सूचना व तकनीकी मंत्री ड. आशीष शेलार ने कहा कि महाराष्ट्र प्रशासन लोकाभिमुख कार्यप्रणाली में पहले से अग्रणी है। 'आई गॉट' (ळक्रज्ञढ) पोर्टल पर प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र शीर्ष पर आएगा। प्रशासनिक सेवाओं को और तेज़, मापनीय व उत्तरदायी बनाने की ज़रूरत है।

राजेश कुमार का वक्तव्य:

प्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार ने कहा कि इज ऑफ लिविंग यानी नागरिकों के लिए जीवन को सरल बनाने की दिशा में प्रशासन को लगातार काम करना चाहिए। अधिकारी और कर्मचारी नई तकनीकें सीखकर सेवाओं को अधिक उपयोगी बनाएं, यही समय की मांग है।

आर. विमला का वक्तव्य:

महाराष्ट्र सदन की आयुक्त आर. विमला ने कहा कि अपर मुख्य सचिव वी. राधा के नेतृत्व और अधिकारियों-कर्मचारियों के उत्साह के कारण महाराष्ट्र ळक्रज्ञढ पोर्टल पर सबसे अधिक प्रशिक्षण लेने वाले राज्यों में शीर्ष ३ में पहुंचा है। टेक वारी' की अवधारणा नवोन्मेषी है और यह सभी स्तरों के अधिकारियों को लाभ देगी।

इस मौके पर आर. विमला ने बताया कि टेक वारी' में मंत्रालय से लेकर ग्राम स्तर तक के अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन की योजना अपर मुख्य सचिव वी. राधा द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन उनके पिताजी के निधन के कारण वे उपस्थित नहीं रह सकीं। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

मंत्रालय परिसर में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों से जुड़े स्टार्टअप्स और मन:शक्ति प्रयोग केंद्र के उपक्रमों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन शिल्पा नातू ने किया.

बीड के नागरिकों को पानी के लिए कब तक तरसाया जाएगा?

बीड, ५ मई (प्रेस विज्ञप्ति)

बीड शहर में तेज़ गर्मी ने पानी की गंभीर किल्लत को और भी भयावह बना दिया है। अधिकतर बोरवेल तेज़ गर्मी के कारण सूख चुके हैं, वहीं मंझलेगांव जलापूर्ति योजना भी पिछले कई दिनों से बंद है, जिससे नलों को पानी देखे हुए २५ दिनों से अधिक का समय बीत चुका है।

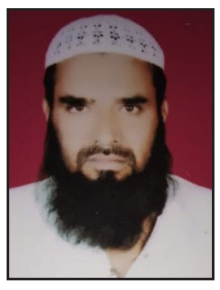

इस संकट के चलते महिलाओं, माताओं, बहनों और बच्चों को पानी की तलाश में घर से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पीने के पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति न होने से नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रशासन की खामोशी ने जनता में नाराज़गी और बेचैनी बढ़ा दी है।

इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए जमीयत उलेमा जिला बीड़ के अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल्ला क़ासमी ने जिला कलेक्टर, नगरपालिका के सीईओ और प्रशासन से अपील की है कि वे तत्काल इस समस्या पर ध्यान दें और नागरिकों को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। यदि पाइपलाइन से पानी देना फिलहाल संभव न हो तो हर गली में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाए ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके।

मुफ्ती अब्दुल्ला क़ासमी ने कहा कि पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। यदि समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।

धारावी के नाम पर मुंबई की ज़मीन हड़पने की नई ईस्ट इंडिया कंपनी' की साज़िश: सांसद वर्षा गायकवाड़

जमीर काजी

। मुंबई

धारावी पुनर्विकास के नाम पर मुंबई की ज़मीन हड़पने की कोशिश एक 'नई ईस्ट इंडिया कंपनी' जैसी साज़िश है। जैसे कभी पुर्तगाल ने मुंबई की ज़मीन अंग्रेजों को भेंट में दी थी, उसी तरह आज प्रधानमंत्री मोदी के ख़ास मित्र अदाणी को मुंबई की ज़मीन तोहफ़े में दी जा रही है-ऐसा तीखा आरोप मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद वर्षा ायकवाड़ ने लगाया है।

वह धारावी बिज़नेस असोसिएशन द्वारा आयोजित जन

आक्रोश मोर्चे में बोल रही थीं। इस मौक़े पर शिवसेना (ठाकरे गुट) के सांसद अनिल देसाई और कांग्रेस की विधायक डॉ. ज्योति गायकवाड़ ने भी भाजपा-शिवसेना सरकार पर तीखा हमला बोला और चेताया कि धारावी को पूंजीपतियों के हवाले करने के विरोध में बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा।

सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, मोदानी और उनकी कंपनियाँ सिर्फ धारावी ही नहीं, बल्कि मीतागर की ज़मीन, कोलीवाड़े, मुंबई के हरित क्षेत्र और यहां तक कि डंपिंग ग्राउंड को भी हड़पने की योजना बना रही हैं। यह सब करने के बाद, धारावी के लोगों को कचरे के ढेर में धकेल दिया जाएगा ताकि पूरी धारावी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर ये कंपनियाँ अपना साम्राज्य खड़ा कर सकें। लेकिन हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, दूसरे राज्यों में भले ही बुलडोज़र राज चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में संविधान का राज है और यहीं चलेगा। मुंबई के लोग तानाशाही के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं।

वॉटर स्ट्राइक के ज़रिए पाकिस्तान को भारत का एक और झटका: चनाब नदी पर बने सलाल डैम के दरवाज़े बंद, सरहद पार जाने वाला पानी रोका गया

नई दिल्ली, ५ मई । विशेष संवाददाता

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चनाब नदी पर बने सलाल डैम के सभी दरवाज़े बंद कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की ओर बहने वाला पानी रोक दिया गया है। इसे सीमा पार की हरकतों पर जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है।

इस फैसले के चलते जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में पानी के स्तर में तेज़ी से गिरावट आई है। वहीं रामबन ज़िले में बगलीहार डैम से पानी बहता देखा गया। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रणनीतिक कार्रवाई की सराहना की है।

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा,

देश के हित में कड़े फैसले लेने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए होती है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सिद्ध कर दिखाया है। हमारे नागरिकों का खून और पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी एक साथ नहीं बह सकते। मोदी जी आतंकवाद के ख़िलाफ़ अडिग हैं।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानिय निवासी दिनेश ने कहा,

हमें ख़ुशी है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे नागरिकों का खून बहाया, सरकार का ये जवाब बिल्कुल सही है। हम सरकार के साथ हैं।

एक अन्य स्थानीय नागरिक ने कहा,

ये बहुत बड़ा और सही फैसला है। हमारी सरकार पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब दे रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया यह साहसिक कदम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक साहसिक और निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा,

आज का भारत दोस्ती भी निभाना जानता है और दुश्मनी भी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।

सिंधु जल संधि की पृष्ठभूमि

भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष १९६० में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि हुई थी। इसके तहत तीन पश्चिमी नदियाँ-सिंध, झेलम और चनाब-पाकिस्तान को, और तीन पूर्वी नदियाँ-रावी, ब्यास और सतलुज-भारत को दी गई थीं। हालांकि, भारत को पाकिस्तान की नदियों से सीमित मात्रा में पानी उपयोग की अनुमति थी।

भारत की कड़ी कार्रवाई

२२ अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में २६ पर्यटक मारे गए थे। यह हमला २०१९ के पुलवामा हमले के बाद का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के चलते कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया था, और सिंधु जल संधि को आंशिक रूप से निलंबित कर दिया गया।

बाद में पानी फिर से छोड़ा गया

सूत्रों के अनुसार, कुछ समय बाद डैम के दरवाज़े खोलकर पानी फिर से छोड़ा गया। जम्मू के अखनूर क्षेत्र में पुलिस ने स्थानीय लोगों को चनाब नदी के किनारे जाने से मना किया है, क्योंकि अचानक बढ़े जलप्रवाह से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।

बारहवीं की परीक्षा में सफल छात्रों को शिक्षामंत्री दादा भुसे ने दी शुभकामनाएं

। मुंबई

जमीर काजी

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित १२वीं (उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र) परीक्षा २०२५ का परिणाम आज सोमवार को मंडल अध्यक्ष शरद गोसावी और सचिव देविदास कुलाल द्वारा पुणे से घोषित किया गया। इस अवसर पर राज्य के स्कूल शिक्षामंत्री दादाजी भुसे ने परीक्षा में सफल हुए छात्रों, उनके अभिभावकों और उन्हें मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

शिक्षामंत्री ने क्या कहा?

शिक्षामंत्री भुसे ने कहा कि बारहवीं की परीक्षा विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद छात्रों के लिए अपने रुचि अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के मार्ग खुलते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि छात्र इस अवसर का भरपूर लाभ उठाकर न केवल अपना, बल्कि देश का भी भविष्य उज्जवल बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह परीक्षा अंतिम मंज़िल नहीं है, इसलिए जिन छात्रों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, वे नए जोश के साथ पढ़ाई में जुट जाएं और आगे चलकर सफलता प्राप्त करें।

परीक्षा परिणाम की मुख्य विशेषताएं

इस वर्ष फरवरी से मार्च २०२५ के दौरान आयोजित परीक्षा में राज्य के ९ विभागीय मंडलों (पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नाशिक, लातूर और कोकण) से विज्ञान, कला, वाणिज्य, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और खढख शाखाओं के लिए कुल १४,२७,०८५ नियमित छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से १३,०२,८७३ छात्र सफल हुए हैं, और कुल सफलता प्रतिशत ९१.८८% रहा।

विभागवार परिणाम

कोकण: ९६.७४% (२२,७९७ छात्र)

कोल्हापुर: ९३.६४% (१,०६,००४ छात्र)

मुंबई: ९२.९३% (२,९१,९५५ छात्र)

छत्रपति संभाजीनगर: ९२.२४% (१,६५,९६१ छात्र)

अमरावती: ९१.४३% (१,३२,८१४ छात्र)

पुणे: ९१.३२% (२,२१,६३१ छात्र)

नाशिक: ९१.३१% (१,४४,१३६ छात्र)

नागपुर: ९०.५२% (१,३६,८०५ छात्र)

लातूर: ८९.४६% (८०,७७० छात्र)

लड़कियों ने फिर मारी बाज़ी

लड़कियों का सफलता प्रतिशत ९४.५८% रहा, जबकि लड़कों का ८९.५१%। यानी लड़कियों की सफलता दर लड़कों से ५.०७% अधिक रही।

प्रावीण्य (मेरिट) से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण: १,४९,९३२ छात्र

सामान्य प्रथम श्रेणी में: ४,०७,४३८

द्वितीय श्रेणी में: ५,८०,९०२

उत्तीर्ण श्रेणी में: १,६४,६०१

शाखानुसार परिणाम

विज्ञान: ९७.३५% (७,१५,५९५ छात्र)

वाणिज्य: ९२.६८% (२,७७,६२९ छात्र)

कला: ८०.५२% (२,८१,६०६ छात्र)

व्यावसायिक पाठ्यक्रम: ८३.२६% (२४,४५० छात्र)

खढख: ८२.०३% (३,५९३ छात्र)

दिव्यांग छात्रों की सफलता दर

राज्यभर से कुल ७,३१० दिव्यांग छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था, जिनमें से ६,७०५ छात्र सफल हुए हैं। दिव्यांग छात्रों की सफलता दर ९२.३८% रही। श्रेणी सुधार/अंक सुधार योजना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र तीन आगामी परीक्षाओं-जून-जुलाई २०२५, फरवरी-मार्च २०२६, और जून-जुलाई २०२६-में श्रेणी सुधार या अंक सुधार के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए छात्र को एक बार में सभी विषयों के साथ परीक्षा में शामिल होना आवश्यक होगा।

सीएम रेवंत रेड्डी के सलाहकार जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने ली समीक्षा बैठक, वक्फ बोर्ड के मुद्दों पर जताई गंभीर चिंता

हैदराबाद,

विशेष संवाददाता

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

के अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति मामलों के सलाहकार जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे केंद्र में रहे और उन्होंने इन पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही।

शब्बीर अली ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके मंत्री काल में वक्फ बोर्ड में जितनी व्यवस्था और पारदर्शिता थी, उतनी पिछले ११ वर्षों में नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों में जिस प्रकार की लापरवाही और अव्यवस्था देखने को मिली है, वह बेहद चिंताजनक है। जो भी व्यक्ति वक्फ संपत्तियों के साथ खिलवाड़ या अनियमितता करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनाब शब्बीर अली ने यह भी ऐलान किया कि वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए अब ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो तेलंगाना वक्फ बोर्ड के इतिहास में पहली बार होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इंशा अल्लाह यह प्रक्रिया न सिर्फ भ्रष्टाचार को रोकेगी, बल्कि वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और बेहतर उपयोग की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

डॉ, शाहीन क़ाज़ी गर्ल्स जूनियर कॉलेज का परिणाम ९७.७७ प्रतिशत

जलगांव (अकिल ख़ान ब्यावली)

सैय्यद नाज़नीन प्रथम,सबा इरम सिरिंज पिंजारी द्वितीय,तो हुरीया खलील शेख ने तृतीय स्थान प्राप्त किया.

जलगांव (अकील खान ब्यावली)

अंजुमन ए खिदमत ए ख़ल्क़ संचालित डॉ.शाहीन क़ाज़ी गर्ल्स जूनियर कॉलेज,का महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड नासिक विभाग कक्षा १२ वीं का परिणाम ९७.७७ प्रतिशत रहा .सैय्यद नाज़नीन नियाज़ अली ने ७८.५० अंक लेकर जूनियर कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया,सबा इरम सिराज पिंजारी ने ७७.५० अंक लेकर दूसरे स्थान पर शेख हुरीया खलील ७४.६७ अंक प्राप्त कर तिसरा स्थान, अल्मास कमरुद्दीन पिंजारी ७४.१७ अंक प्राप्त चतुर्थ तो मारीया तबस्सुम शेख़ मुख्तार ७२.८३ अंकों के साथ पंचम स्थान पर रहे .सफलता प्राप्त करने वाली छात्राओं और शिक्षण कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले शिक्षकों को संस्था के अध्यक्ष अल्हाज खालिद बाबा बागबान, उपाध्यक्ष अल्हाज अब्दुल मजीद सेठ ज़केरिया,सचिव अल्हाज शेख हसन नूर मुहम्मद,सह सचिव जाहिद भाई शाह, कोषाध्यक्ष डॉ.अल्हाज ताहेर शेख,डॉ.एजाज़ शाह आसीफ इकबाल बागबान और प्रिंसिपल तन्वीर जहां शेख ने बधाई दी और भविष्य में इसी प्रकार की सफलता की आशा व्यक्त की.

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com